been submitted to the Railways. We look into them as to which are feasible in terms of our parameters and take further action. I think with these words, I must say that the project Jiribam-Imphal which he was mentioning, was only in lieu of Diphu-Karang project, and it has been taken up. It is more economical in terms of cost as well as the years of completion, clearance etc.

SHRI T. R. ZELIANG: The distance between Jiribam to Imphal is 223 kms. And again Jiribam to Diphu is another 300 kms. So, the entire length of road is more than 500 kms. whereas Diphu to Karong, Imphal is within 200 kms. So, will people prefer to travel *via* Jiribam-Silchar to Diphu-Guwahati, the main line of the country or will people prefer to go through this Nagaland-Karong-Imphal which is 200 kms.? There is a difference of 300 kms. I am talking about that, Sir. That is why I am asking whether you are going to restore all the projects which have taken 20 years to get approval. Now after approval you are talking about Kohima. How long will it take to get approval? You are going to scrap it. This is a very tricky one. ...(*Interruptions*)... We can never get it. The Government should reconsider to restore all projects which were already approved ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, would you like to respond?

SHRI R. VELU: This has got a different angle about roads and other things. This will be examined and further action will be taken if it is feasible. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has told that he will examine it. Next question.

Points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on 17th February, 2006 to Unstarred Question No. 38 regarding "Pollution in Ganga"

श्री उपसभापतिः श्री कमाल अख्तर। आज जरा प्रिसाइस बोलिएगा।

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सभी लोगों को जल्दी जाना है, लेकिन आज जो सवाल

हमारे सामने है, वह करोड़ों लोगों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ सवाल है, साथ ही साथ हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ यह सवाल है। मैं जानता हूं कि समय कम है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सवाल को उठाने के लिए आप मुझे पूरा समय देंगे।

उपसभापति जी, आपने करोड़ों लोगों की भावनाओं, स्वास्थ्य, रोजगार एवं जीवन देने वाले विषय पर चर्चा स्वीकार करके जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस देश में जीवन के लिए नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। गंगा, यमुना, सतलुज, सरस्वती, रामगंगा इत्यादि ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो हिन्दुस्तान का गौरव हैं साथ ही इनसे देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये करोड़ों लोगों को रोज़गार देने का भी काम करती हैं, करोड़ों लोगों का जीवन इन्हीं नदियों से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार ने इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई हैं और इन पर अरबों-खरबों रुपया खर्च किया।

मान्यवर, यदि आपने कभी यमुना नदी को देखा हो, जो दिल्ली से होकर गुजरती है, वह यमुना नदी आज नदी नहीं रह गई है, वह एक गंदा नाला हो गई है। आज पूरी दिल्ली का कचरा उस नदी के अन्दर डाला जाता है। उसके दाएं-बाएं इतना अधिक अतिक्रमण हो गया है कि जिस यमुना में नहाने के बाद लोग अपने आपको धन्य महसूस करते थे, अपने गुनाहों को माफ करवाने के लिए लोग उसमें जाकर नहाते थे, लेकिन आज यदि कोई आदमी उसमें जाकर नहा ले, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि उसको कोई न कोई चर्म रोग हो जाएगा।

जहां तक यमुना नदी का संबंध है, उसे तो सारी सरकारें एवं अन्य सभी लोग भी मिलकर बचा नहीं सके, लेकिन उपसभापति जी, आज सवाल गंगा का है। गंगा वह नदी है जो हरिद्वार से निकलने के बाद यदि कहीं पर सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, सबसे पहले जहां उसे प्रदूषित किया जाता है, तो वह मेरा क्षेत्र है। यदि आपको कभी रास्ते से गुज़रते हुए गजरौला या मुरादाबाद जाने का मौका मिला हो, आप वहां जाकर देखिए कि जब गजरौला आने से 10 किलोमीटर पहले दुर्गन्ध आने लगती है, तब वहां से निकलने वाला हर आदमी यह समझ लेता है अब गजरौला आ गया। इसकी कुछ जिम्मेदार फैक्टरीज हैं और वे फैक्टरीज हैं-जुबलेंट आर्गेनिस, रामगंगा फर्टिलाइजर, जे०के० डेरी एंड फूड्स और इसके अलावा वहां कई यूनिटें ऐसी हैं जो वहां पर निकलने वाली एक महत्वपूर्ण बगद नदी के अंदर अपना रासायनिक कचरा डालती हैं और उसको प्रदूषित कर रही हैं। यही नदी आगे जाकर कच्चला घाट के अंदर जो 70 किलोमीटर जाती है, उस 70 किलोमीटर के बाद गंगा में जाकर यह नदी गिरती है। इस प्रदूषण की सबसे अधिक जिम्मेदार जुबलेंट आर्गेनिस

और रामगंगा फर्टिलाजर हैं। मान्यवर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और अपने बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि भोपाल जैसा खतरनाक कांड अगर कहीं पर दोबारा दोहराया जाएगा, अगर सरकार नहीं जागी तो मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वह गजरौला के अंदर, जे॰ पी॰ नगर के अंदर दोहराया जाएगा, क्योंकि आज पूरे वातावरण के अंदर इतनी तरह की गैसेज औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़ी जा रही हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अमरोहा जो आम की फसल के लिए मशहूर था, परन्तु आज इन फैक्टरीज के प्रदूषण से हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए की आम फसलें बर्बाद हो गईं। उस क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी आम की फसल नहीं उगा सकते। उसके 10 किलोमीटर के अंदर उस बगद नदी के बराबर में जो दो सौ गांव पड़ते हैं, उन दो सौ गांवों के अंदर एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां पर आपको पीने का पानी साफ मिल सके। वहां पर आप जाकर देख लीजिए कि जब गांव के वासी नल चलाते हैं तो रंगीन पानी निकलता है, जहरीला पानी निकलता है। आज गजरौला क्षेत्र के लोगों के अंदर तरह-तरह के हृदय रोग, नपुंसकता, आंखों के रोग, चर्म रोग, फेफड़ों की बीमारी ऐसी तमाम बीमारियां इन रासायनिक गैसों की वजह से हो रही हैं तथा वहां पर लोग पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर हैं। उपसभापति महोदय, फैक्टरी से निकलने वाले पानी ने बगद नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि उसमें कोई भी जीव-जन्तु जीवित नहीं है और जहां पर हजारों लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे वे भी बेकार हो गए हैं। आज पूरी नदी के अंदर आपको पानी के अंदर रहने वाला एक जीव भी जिन्दा नहीं मिलेगा। साल के अंदर हजारों मवेशी वहां के जहरीले पानी को पीकर मर जाते हैं। जो किसान उस पानी के अंदर से होकर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको चर्म रोग हो जाते हैं, कोढ़ जैसे भयानक रोग भी उनको हो जाते हैं। उपसभापति महोदय, सबसे जो खतरनाक चीज है वह यह है कि इस फैक्टरी का जो प्रबंध तंत्र है वह इतना मजबूत है कि इस देश की सरकार के ऊपर और मुझे कहना नहीं चाहिए कि सदन के जो आदेश हैं, उनकी अवहेलना तक की जाती है। 1997 के अंदर जस्टिस गुमान मल लोढा जी के नेतृत्व में 17 सदस्यों की एक संसदीय उपसमिति बनी और उस समिति ने वहां जाकर प्रदूषण का सर्वे किया, गांव वालों की राय ली, बगद नदी का भी निरीक्षण किया। उपसभापति महोदय, आज प्रबंध तंत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जो पानी के नमूने लिए गए उन नमूनों को वहां पर चुरा लिया गया। तो जस्टिस गुमान मल लोढा जी ने वहां कहा कि जिन प्रबंध तंत्र के लोगों ने पानी के नमूने चुराए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन गजरौला क्षेत्र के सी॰ओ॰ की 7 साल की तफ्तीश के बाद आज तक एक भी अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बताना चाहता हूं कि यहीं इसी सदन के अंदर आपके सामने वहां का दूषित पानी हम लोगों ने दिखाया था। माननीय उदय प्रताप जी ने भी इस सदन में इस मामले को उठाया था। लोक सभा के अंदर माननीय राम गोपाल यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद यहां से निर्देश दिया गया जिस पर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की टीम भेजी गई तथा फैक्टरी प्रबंधकों द्वारा दी

गई रिपोर्ट के आधार पर ही इन अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की गई और इस तरह से गलत तथ्यों की रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा सदन में दी जाती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए गए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट को चलाया नहीं जा रहा है और रात को प्रदूषित पानी बगद नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। जो ट्रीटमेंट लैगून खोद लिए गए हैं, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जाकर देखिए कि इन लैगून का जहरीला पानी, फैक्टरी से निकलने वाला कचरा, आज जमीन के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वहां का जो जल स्तर है तथा भूमि के नीचे वाला जल पूरी तरह से दूषित हो गया है। आज वहां का प्रबंध तंत्र इतना मजबूत है, सरकार के ऊपर इतना मजबूत है कि आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हम लोगों ने गुमान मल लोढा जी की रिपोर्ट मांगी, उसके ऊपर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी तो आज लायब्रेरी के अंदर समिति की रिपोर्ट नहीं है, मंत्रालय के अंदर रिपोर्ट नहीं है। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, तो गजरौला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लाखों लोगों की जान बचानी है, लाखों लोगों का जीवन बचाना है और हिन्दुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे लोगों के जज्बात हुड़े हुए हैं, उस नदी को प्रदूषण से बचाना है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार फिर, आप इस सदन की एक संसदीय उप समिति बनाकर इसकी जांच करवाइये अथवा आप किसी ऐसी संस्था से जांच करवायें जिसके अंदर जनप्रतिनिधि हों, जिसके अंदर मानवाधिकार की संस्थाएं हों, जिसके अंदर उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि हों, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारी हों। आप कोई ऐसी जांच कमेटी बनायें जिसके माध्यम से वहां की जांच होने के बाद, वह्यं की जनता को राहत मिल सके और जो फैक्ट्रयों द्वारा जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो तरह-तरह की रासायनिक गैस वहां इकट्ठी की जा रही हैं, उसके कारण आने वाले समय में, होने वाली तबाही से, आज गजरौला को बचाइयेगा। धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः डा॰ चन्दन मित्र।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, मैं..।

श्री उपसभापतिः वह उन्होंने बोल दिया है, आप समर्थन कर दीजिए।

श्री नन्द किशोर यादवः उपसभापति महोदय, श्री कमाल अख्तर जी ने जो यहां पर सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपसभापतिः मैं आपको बाद में बुलाता हूं। डा॰ चन्दन मित्र।

DR. CHANDAN MITRA (Nominated): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. I am really grateful that we are having this debate. The matter has been raised during the Question Hour on Friday and the hon. Minister was also present at that time. So, I am sure, you and other hon. Members of the House are fully aware of the very serious situation prevailing in the holy city of Varanasi which is the holiest spot, I would say, not only for the Hindu community but for the entire country. The situation of Ganga at Varanasi, which has been, from time immemorial, the place where people have come and paid respects not only from all over the country, but all over the world is in a pathetic condition, despite twenty years of the GAP. It is truly, I think, ironic that we are having this discussion just the day after the death anniversary of Shri Rajiv Gandhi who was the initiator of the Ganga Action Plan twenty years ago and raised so much hopes and aspirations of the people of India by undertaking this Plan.

Sir, I speak on this subject with authority of having visited Varanasi to examine the situation on the spot only two months ago as a part of the delegation in which Mr. Tariq Anwar, a fellow Member of this House and the then Member, Mr. Balbir Punj were also there. There were three Member from the Lok Sabha. We went to do on the spot survey of the situation in Varanasi. Sir, the situation is so serious that the river in Varanasi, leave alone the water being fit for drinking, it is not even fit for bathing according to the WHO guidelines. The river is on the verge of dying. The oxygen level in the river has fallen to precarious proportions. The fish are dead. And, if you go by a boat, along the river, you find bubbles rising from methane gas. That happens as a result of the pollution and garbage that is being disposed into the river. Sir, we went on a boat from Varuna to Asi. The city of Varanasi gets its name from these two rivers. Varuna and Asi become as Varanasi. So, these two rivers flank the holy city of Varanasi. When you reach the point where river Varuna discharges into river Ganga, you get a putrid smell, because the entire garbage is coming into the river Ganga. At the other end, the Asi river is no longer a river. It is a pure drain. It is as polluted as Najafgarh drain here in Delhi and other such drains. All this water is flown into the river. Sir, all along the route, sewage pipes discharging water and untreated waste into the river. All this was supposed to have been checked by water treatment plants. Several plants have been built along the way.

But, those plants do not operate. There is no electricity to begin with And, these plants are heavily dependent on electricity and, since there is a power shortage in UP, as in the rest of the country, the plants are inactive most of the time. In fact, at the time of the heaviest sewage disposal in the morning, there is power cut and water comes in untreated and flows into the river.

So, this is for everybody to see. It is no new development. It has been going on for years and no plan has so far been made on how to stop the discharge of absolutely untreated sewage into the river.

Sir, the specific point which I want to make, and on which I would seek the Minister's response is this. There is a plan which was submitted several years ago as a solution to this. The solution is very simple. It is not a very costly solution. The solution was to construct a drain along the *ghats* of Varanasi. Starting from the Asi River to the Varuna River, you go along the *ghats*, and a cover drain was to be constructed so that all the sewage that is flowing into the river could come into this. As you know, the city of Varanasi is at a height from the Ganga. All the sewage water that is coming in should discharge itself into this particular drain and the drain would run along the entire length of the riverfront of Varanasi. It would then be taken by a pipe across the river and be discharged in an uninhabited island in the middle of the river. Now this plan, with Japanese technology, has been there for several years. It is a far less costly plan than what is being proposed by the State Government, that is, to build more sewage treatment plants. Sir, sewage treatment plants have been set up and they have been ineffective. Now, this simple technology which will relieve the problem almost completely, has not been implemented. For seven years a litigation has been going on between the Uttar Pradesh Jal Nigam and the residents of Varanasi, including the Varanasi Municipal Corporation which had passed a unanimous resolution approving this plan. Now, according to the Nagar Palika Act, it should be the responsibility of the Varanasi Municipal Corporation to devise a plan, and for the Centre to allocate the funds through the State Government for its implementation. By ignoring the local authorities and not taking the local factors into consideration, this scheme of bringing in more machines, more water disposal plants, sewage disposal plants and consuming power, totally impractical, which will cost a lot of money. We have already seen that this plan is ineffective. I would like to know from the hon. Minister: What

is its status here and why it is not being implemented? We MPs submitted a memorandum when our delegation went there at the invitation of the Sankat Mochan Trust, which is doing a lot of good work there. Mahant Virbhadra Mishraji has been at this for so many years. He still bathes in the river everyday, which, actually, very few people risk doing now. As an hon. Member was saying, like in the Yamuna, if you actually have a holy dip in the Ganga today, you will come out an unholy man because of the rashes that are likely to erupt in your body. In this situation, given the very serious nature of the crisis and the faith of millions and millions of people that is involved, this matter has to be taken up on a war footing. The Ganga Action Plan phase II for Varanasi has been held up for so many years. Sir, I appeal to the Minister to give urgent consideration so that the Ganga that has become maili is restored to a situation where we can still say "गंगा तेरा पानी अमृत।"

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, this Ganga Action Plan was later renamed as the National River Conservation Plan. It was expected to cost Rs. 3,780 crores, but till March 2006, an expenditure of Rs. 2,500.39 crores reported to have been incurred. Now, Sir, it has just now been mentioned that the plan target of STP, that is, Sewage Treatment Plan, was not achieved. Whatever little was achieved, that also went down due to very poor maintenance. Then, Sir, at the stretch between Kanpur-Allahabad-Kannauj, water quality of Ganges has been monitored. Pollution has been found to be higher than the limit. Due to the existence of a large number of leather and chemical industries, water is being further polluted.

Pollution in the Yamuna River is also a matter of grave concern. The quality of water is below standard in Delhi due to heavy discharge of sewage water. The same is the situation in Agra. It is like a dirty canal. I had an opportunity to visit those places, and I found that the overall progress is poor. Even some of the facilities created like electric crematorium etc., become non-operational shortly after commissioning.

In Allahabad, Haridwar and Kanpur, such crematoriums started in 1991, and stopped operating in 1997, due to non-payment of electricity bills, etc. I remember that once the CAG also made a very serious comment against the Ganga Action Plan. Then, it is found that half-burnt dead bodies are being thrown in the Ganges, because of the non-functioning of the electric

crematorium; and, the people's temperament is also like that. There is lack of scientific temperament. So, that is further polluting the river water. Then, the problem of solid waste management is there. I would like to inform the Minister that even in the Mid-Term Appraisal Report, it has been advocated that an independent evaluation would be useful for such stocktaking, because a very huge amount has been spent. The meaningful coordination between the State Governments and local bodies with active participation of the Ministry of Environment and Forests is necessary. I want a definite answer from the Minister. Thank you.

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : सर, माननीय सदस्य ने देश की प्रमुख नदियों में औद्योगिक प्रदूषण, गंगा नदी और बगल में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में चिंता जाहिर की है। इसके साथ अन्य माननीय सदस्यों ने भी वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान के तहत कार्य न होने से पानी की क्वालिटी खराब होने की बात कही है और अन्य सदस्यों ने कानपुर और कन्नौज में स्थिति खराब होने के बारे में जिक्र किया है। सर, गंगा की सफाई का अभियान स्वर्गीय राजीव जी ने इस देश में 1985 में प्रारम्भ किया था। गंगा नदी और दूसरी नदियां लोगों की आस्था का केन्द्र रही हैं, जीवन रेखा रही हैं, लोगों को सिंचाई का पानी मिलता और पीने का पानी भी मिलता और हमारा इन्वायरन्मेंट भी अच्छा रहता है। जिस प्रकार शरीर में धमनियों में खून बहता है, यदि अच्छा खून नहीं है तो आदमी अस्वस्थ हो जाएगा, इसी प्रकार सारी नदियों का रोल किसी भी देश में रहता है। सर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नदियों के उपयोग हैं, उसके अलावा उनमें किस प्रकार से प्रदूषण होता है। जो डोमेस्टिक वाटर वेस्ट है, उससे प्रदूषण होता है, जो इंडस्ट्रीयल वाटर होता है, उससे प्रदूषण होता है। यही नहीं इस तरह के नॉन प्वाइंट सोर्सेज भी होते हैं, जिनका हमें पता ही नही चलता है, runoff from agricultural fields, dumping of burnt and half-burnt bodies, जैसे अभी माननीय सदस्यों ने बताया है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रदूषण के कारण हैं। अभी Central Pollution Contol Board ने सारे देश में जो पॉल्युशन का आकलन किया है, 29 हजार एमएलडी, उन लोगों ने यह बताया है कि देश में यह पॉल्युशन हैं चाहे वह नदियों से हो, चाहे वैट लैंड्स है, चाहे झीलें हैं या ऐसी नदियां हैं जो पेरिनियल हैं, नॉन पेरिनियल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मेग्नीट्यूड है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हैंडल करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की जरुरत है। सर, पानी स्टेट सब्जेक्ट है। इन्वायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंकर्रेंट सूची में है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, केन्द्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अर्बन बॉडीज हैं और जनरल पब्लिक है, इन सबके सहयोग से ही इस समस्या का हल पाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले 1985 में राजीव जी ने गंगा एक्शन प्लान फेज-1 प्रारंभ किया, जो सन् 2000 में कम्पलीट हुआ। गंगा एक्शन प्लान फेज-2 1995 में प्रारम्भ किया गया और उसमें भी यमुना फेज-1 1993 में चालू हो गया।

इस Magnitude को देखकर भारत सरकार ने 1995 में एक decision लिया कि इन सारी नदियों की सफाई के काम को National River Conservation Plan के तहत ले लिया जाए। आज की तारीख में सारे देश में इसी प्लान के तहत नदियों का conservation चल रहा है। इसमें Ganga Action Plan II की 5 नदियां है। और 29 दूसरी नदियां हैं। इस प्रकार आज देश में 34 नदियों में conservation का काम चल रहा है, 160 towns में ये schemes दी गई हैं और 20 राज्यों में इनका कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारी जो approved cost है, वह 4,735 करोड़ रुपए की है। इसमें funding pattern भी है – आज की तारीख में 70 प्रतिशत Government of India दे रही है और 30 परसेंट स्टेट्स देती हैं। पहले Ganga Action Plan, Phase I 100 परसेंट भी चला है, फिर 1997 में 50:50 हुआ, आज यह 70:30 चल रहा है। हम Japan Bank of International Cooperation से soft loan ले रहे हैं, वह 85:15 पर चल रहा है।

उपसभापति जी, यह हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में National River Conservation Plan के तहत 932 schemes चल रही हैं, जिनमें से 570 पूरी हो चुकी हैं। अभी 5,364 MLD को handle करने का प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसकी approved cost 4,735 करोड़ रुपए की हैं इसको पूरा करने के लिए हमारे पास अभी तक 10th Plan को जो fund allocation है, उसमें भी हमें 1,672 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है। गंगा और यमुना की बात अभी यहां हो रही थी। गंगा में first phase, वर्ष 2000 में complete हुआ, अभी इसका second phase चल रहा है। इसी तरह यमुना का first phase, वर्ष 2003 में पूरा हो गया था। आज भी गंगा और यमुना का जो pollution load है, उसको handle करने के लिए 3,064 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमारे रुड़की के इंस्टीट्यूट ने हमारे पास कुछ और नदियों के pollution की रिपोर्ट भेजी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आज जितनी हमारी approved cost है और जो pollution load है, आज की तारीख में इन सबको handle करने के लिए 7,358 करोड़ रुपए की requirement है। अभी गंगा की बात आई। Central Pollution Control Board ने, 1985 में जब गंगा नदी में pollution load आंका था, तो वह 1,340 MLD था। उस वक्त हमारे पास पैसे की कमी थी। उस समय 882 MLD load के लिए यानी 65 परसेंट load के लिए ही पैसा sanction किया गया था। उसके पूरा हो जाने के बाद, आज की तारीख में 2,538 MLD का pollution load है। Ganga Action Plan, First Phase में 882 MLD और Second Phase में 780 MLD handle करने के बाद भी, 876 MLD फिर भी रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि गंगा के पूरे pollution load को समाप्त करने के लिए, आज के हिसाब से 1,300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

उपसभापति जी, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहूंगा कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज गंगा के बेसिन पर और उसकी tributaries पर 40 से 50 करोड़ आबादी, upstream area में रहती है। यह खाली गंगा का सवाल नहीं है, यह उसमें मिलने वाली नदियों का भी सवाल है। वहां से भी pollution आ रहा है। इन सबको treat करने की आवश्यकता होगी। इतने बड़े भारी क्षेत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है और वहां से जो pollution load आ रहा है, जो म्युनिसिपल सीवेज आ रहा है, उसको handle करने के लिए हमें capacity develop करनी है। माननीय सदस्यों ने बिल्कुल वाजिब कहा कि आपने बहुत सारे capacity sewage treatment plants बना दिए हैं। भारत सरकार, राज्यों सरकारों को और म्युनिसिपल बॉडीज को supplement करती है, support करती है, वन टाइम। जो भी facilities create हो जाती हैं, उनकी running और उनकी maintenance कि जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मैं कई सदस्यों से सहमत हूं, जिन्होंने बताया कि facility create हो गई, लेकिन उसके बाद उसको चलाया नहीं गया। इसमें सबसे बड़ा जो defaulter है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, वे यूपी सरकार को तीन चिट्ठी लिख चुके हैं – 2004 में लिखी, 2 जून 2005 और अगस्त 2005 में। उन्होंने यही कहा है कि आपकी जो facilities create हो गई हैं, उनको maintain कीजिएगा, उनको बिजली दीजिएगा और उनको चलाइए, अन्यथा अगर ये facilities create हो गईं और अगर untreated water नदियों में जाएगा, तो facility create करने से क्या हुआ! मुझे अभी अधिकारियों से जानकारी मिली है कि इस साल यूपी ने अपने बजट में भी इस चीज के लिए पैसा रखा है। कई स्टेट्स ने अच्छा काम किया है। उत्तरांचल ने, जो facilities create हुई हैं, उनका फायदा उठाया है, पानी शुद्ध हुआ है। हरियाणा में जो facilities create हुई हैं, उससे यमुना का पानी अच्छा हुआ है। वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया है। कहने का मतलब यह है कि सारे stakeholders को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे म्युनिसिपैलिटीज हों, सबको मिल कर काम करना पड़ेगा। पब्लिक में general awareness भी लानी पड़ेगी, सब लोगों में लानी पड़ेगी, ताकि नदियों का पानी दूषित नहीं हो।

सर, मैं बिना संकोच यह भी बताऊंगा कि वाराणसी की बात आई। वाराणसी में अभी गंगा का second phase चल रहा है, उसके अन्दर 160 कस्बों को इसमें लिया गया है, जिसमें वाराणसी भी है। उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज में भी वाराणसी में काम चल रहा है। Japan Bank of International Co-operation से वाराणसी के लिए 552 करोड़ का soft loan लिया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के साथ agreement हो गया है। DPRs कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं, process में चल रही हैं। अभी इसके cabinet approval की कार्रवाई चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि यह स्कीम जितनी जल्दी लागू हो जाएगी, इस financial year के end तक हो जाएगी, तो वाराणसी का जो level है, वह और बढ़िया होगा।

काम चल रहा है। महोदय मेरा यह मानना है कि फेज 2 से गंगा और बेहतर होगी और दो-तीन तरह के लोन वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ के लिए आ रहे हैं। यह सारी कार्यवाही मंत्रालय से हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि इस सब से हम गंगा के पानी को और बेहतर बना सकेंगे।

महोदय, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। मैंने बीच में उस दिन भी सवाल का जवाब दिया था कि फंड्स की जरूरत है। हम ने दो साल में 75 करोड़ रुपए गंगा फेज 2 में दिए हैं और पिछले 6 साल में, अभी हमारे उधर के भाई नहीं बैठें ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): हम आप को बैठे दिखायी नहीं दे रहे?

श्री नमो नारायण मीणा: उन्होंने 6 साल में 222 करोड़ ही दिए थे। यह प्रोग्राम राजीव गांधी जी ने चलाया और हम ने ज्यादा फंड्स दिए हैं। हम आगे भी गंगा के पानी को शुद्ध करने के लिए और भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस के लिए लोन ला रहे हैं और सब की मदद से काम कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स की वजह से गड़बड़ी हो रही है। मैंने आप को यू॰पी॰ के बारे में बताया कि वहां से मेंटेनेंस और दूसरी चीजें नहीं हो रही हैं। अगर वे सब होंगी तो मेरा मानना है कि गंगा के बारे में धारणा है कि गंगा शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, इसे हम भी चाहते हैं और सारा देश चाहता है। महोदय, यह राजीव जी का सपनां था जिस पर यू॰पी॰ए॰ की इस सरकार में और डा॰ मनमोहन जी के नेतृत्व में और ज्यादा कार्य होगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री कमाल अख्तर: सर, एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने चर्चा का जवाब नहीं दिया, यू॰पी॰ए॰ और राजीव जी के सपने के बारे में सदन को अवगत कराया। सर, मैंने अपने क्वैश्चन के अंदर जुबिलिएंट ऑर्गेनिक्स, गजरौला का जिक्र किया था जहां से गंगा की शुरूआत होती है। उस में जस्टिस घुम्मन मल लोढ़ा की 17 सदस्यीय समिति बनी।

इसकी रिपोर्ट मंत्रालय के पास है। जब कोई गम्भीर समस्या है, जहां लाखों लोगों की जान का खतरा है, तो मंत्री जी या सरकार कितने दबाव में है, यह मंत्री जी के स्टेटमेंट से जाहिर हो गया कि उन्होंने एक बार भी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: वे जवाब दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर: सर, सर, एक मिनट ...(**व्यवधान**)... मेरी बात पूरी होने दीजिए, सर। मेरा क्वैश्चन पूरा होने दीजिए। मंत्री जी बाद में जवाब दे देंगे, मेरा क्वैश्चन पूरा होने दीजिए, सर।

मंत्री जी कितने दबाव में हैं, यह इस बात से जाहिर होता है कि एक क्वैश्चन पर उन्होंने एक बार भी ऐसी किसी भी जांच का नाम नहीं लिया कि हम यह जांच कराने को तैयार हैं। हम लोगों ने मांग की है कि आपका और राजीव जी का सपना गंगा को साफ कराने का है, अगर आप

सर, माननीय सदस्य ने एक controversy के बारे में बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट जो प्रस्ताव भेजती है, हम उनको मंजूरी देते हैं। उनके जल निगम और स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के बीच आपस में कुछ मामला था, वह सुप्रीम कोर्ट में भी गया। वह वहीं कहीं 5-6 साल तक अटक गया। लेकिन उनकी 41 करोड़ के आसपास की जो स्कीमें थीं, वे चालू हो गई हैं, उनसे भी improvement होगा। भारत सरकार के पास स्टेट गवर्नमेंट जो प्रस्ताव बनाकर भेजती है, हम उनकी मंजूरी करते हैं और हमने इनको मंजूरी दे दी है, loan agreement sign हो गया है। इससे स्थिति ठीक होगी।

सर, गंगा Phase-I में जो achievement हुई हैं, उनके बारे में एक perception हो गया है कि नदियों का जल सही नहीं हो पा रहा है। उसके अन्दर कुछ न कुछ गड़बड़ी है।

उस के अंदर कुछ-न-कुछ गड़बड़ी है। मैं माननीय सदस्यों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं हमारे मंत्रालय का mandate, "bathing quality" है। Drinking के लिए तो आप को साफ करना पड़ेगा।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि गंगा के बारे में हमारे चार रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं – सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आई॰आई॰टी॰ कानपुर, लखनऊ की संस्था रिसर्च सेंटर और बी॰एच॰ई॰एल॰। ये रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस वाटर की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। हम ने गंगा के ऊपर 27 मॉनीटरिंग स्टेशंस लगा रखे हैं जो वाटर क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। उन की रिपोर्ट के आधार पर ऋषिकेश से कन्नौज अपर-स्ट्रीम तक वाटर क्वालिटी बी॰ओ॰ और बी॰ओ॰डी॰ हैं। उन की बी॰ओ॰ और बी॰ओ॰डी॰ में 1986 के फिगर्स के बाद 2005 के फिगर्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। इसी प्रकार इलाहाबाद डाउन स्ट्रीम से लेकर उलबेरिया तक बी॰ओ॰ और बी॰ओ॰डी॰ में 86 के मुकाबले इम्प्रूवमेंट है। कन्नौज और इलाहाबाद डाउन स्ट्रीम में भी 86 के मुकाबले इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी डिजायर्ड जितना होना चाहिए, उस से कम है, सुधार की गुंजाइश है। इन में कानपुर, इलाहबाद, लखनऊ व वाराणसी के लिए तो एग्रीमेंट हो चुका है। हमारी सरकार ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ के लिए 1100 करोड़ रुपए का और लोन उन के सामने पोज किया है ताकि उन से एग्रीमेंट होकर और सोफ्ट लोन मिले। इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ की समस्या इस से और अच्छी तरह हल होगी।

महोदय, हमारी सरकार इस संबंध में पूरा भरसक प्रयास कर रही है। यह राजीव जी का सपना था कि गंगा नदी साफ हो। उस में पहले फेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरे में 160 कस्बों में काम चालू हो गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा के कोर्स में 13 स्कीम्स सैंक्शंड हो चुकी हैं, उत्तरांचल में 37, झारखंड में 2, बिहार में 18, बंगाल में 165 और कोलकाता में टेनरीज के लिए तीन स्कीम्स हैं। इस तरह फेज 2 में कुल 268 स्कीम्स गंगा फेज 2 में सैंक्शंड कर दी गयी हैं। इस पर

राजीव जी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो पूरा करिए, लेकिन कम-से-कम उन संस्थाओं के खिलाफ, जो गंगा को, जो राजीव जी के सपने को खराब कर रहे हैं, उन संस्थाओं के खिलाफ कोई जांच की घोषणा आप करें, तो हम मानेंगे कि वाकई आप लोग गम्भीर हैं और राजीव जी का सपना पूरा करना चाहते हैं।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, माननीय सदस्य को जो मैंने स्टेटमेंट दिया है ...(**व्यवधान**)..

श्री कमाल अख्तर: यह गलत है सर, यह रौंग है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, जो मैनेजमेंट द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय और केन्द्रीय बोर्ड को लिख कर दिया गया है। यह वही स्टेटमेंट है। मैं इस सदन के अन्दर कहता हूं और मैं आज भी इतनी बड़ी बात कह कर जा रहा हूं कि आप संसदीय समिति की टीम भेज दीजिए या उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, अगर वहां पर यह नहीं पाया गया, जो कि इन्होंने लिखा है कि यह बारहमासी नहीं है, लेकिन आज भी आप जाकर देख लीजिए कि वहां पर पानी बहता है। आप आज भी जाकर देख लीजिए कछला घाट पर बगद नदी गिरती है। वह बहुत महत्वपूर्ण नदी है। मैं वहां पैदा हुआ और जहां तक मैं जनता हूं कि वहां के ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में केन्द्रीय बोर्ड की समीक्षा बिल्कुल फर्जी है और सिर्फ असत्य है। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने वहां से भारी मात्रा में पैसा लेकर मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेज दी है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर अनुरोध है कि अगर आप राजीव जी का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप वाकई समर्पित हैं, तो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड से अलग कोई जांच समिति बने या घुम्मन मल लोढ़ा जी की समिति की रिपोर्ट निकलवा कर दोबारा टेबल करा दीजिए। जस्टिस घुम्मन मल लोढ़ा जी की जो समिति बनी है, उसी तरह की एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाकर वहां पर जांच करवाई जाए। वहां के जो लाखों-करोड़ों लोग बरबाद हो गए और वहां आने वाले समय में जो भोपाल जैसी पुनरावृत्ति होने वाली है, उसके लिए, उस जनता के लिए आप जवाब दें, तो ज्यादा बढ़िया होगा।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मैंने माननीय सदस्य को अपने स्टेटमेंट में, जो आपने मैसर्स जुबिलिएन्ट आर्गेनिक्स लिमिटेड, गजरौला और वहां और जो दूसरी यूनिट्स हैं तथा और जिन्होंने काम किया है, उसके संबंध में प्रश्न उठाया था, तो हमारी ओर से गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली कुल 187 उद्योगों की बात की गई, जिनमें से 112 उद्योगों में effluent treatments plant लगाए गए हैं, जो कार्य कर रहे हैं और हमने 75 उद्योगों को बन्द कर दिया है।

इसी प्रकार माननीय सदस्य जिसको रेफर कर रहे हैं, मैसर्स जुबिलिएन्ट आर्गेनिक्स लिमिटेड, गजरौला का, तो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो सवाल थे कि वह नदी बारहमासी नहीं है। उसमें किसी प्रकार का औद्योगिक बहिस्राव, पॉल्यूशन का निस्तारण नहीं होता है। अगर माननीय सदस्य को किसी प्रकार की कोई कम्प्लेंट है, कोई किसी तरह की बात है, तो आप बता रहे हैं, उसको मैं देख लूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर: सर, सदन में यह मामला उठा है। यह हम भी जानते हैं कि कोई कम्पलेंट हमने मंत्री जी को लिख कर दिया, तो उनका जवाब आ जाता है कि हम देख रहे हैं। अगर सदन में मामला उठा है, तो मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि कौन-सी उच्च स्तरीय समिति से वहाँ की जाँच करा रहे हैं? कौन-सी पार्लियामेंटरी ज्वायंट एक्शन कमेटी बनाकर दोबारा जाँच करा रहे हैं? तब तो इसका कार्य सार्थक है, तभी राजीव जी का सपना पूरा हो रहा है, नहीं तो बातों से राजीव जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over. The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at fourteen minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 23rd May 2006.

MGIPMRND—2718RS—24-01-2007